प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 38/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे में संशोधन को अधिसूचित किया और इसे जारी किया।

इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में टेलीविजन चैनलों को सूचीबद्ध करने और डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल प्रणाली में अपग्रेडेशन करने पर जारी अनुशंसाएं की।

नई दिल्ली, 08th जुलाई, 2024 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2024 (2024 का 01), दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणाली) (छठा संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 04), दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणाली) (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 03) जारी की तथा साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को 'इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में चैनलों की सूचीबद्ध करने और डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल प्रणाली में अपग्रेडेशन करने' पर अनुशंसाएं भी जारी की हैं।ये संशोधन, कुछ खंडों को छोड़कर, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के बाद लागू होंगे।

2. केबल टीवी क्षेत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण के अनुरूप, भादूविप्रा ने दिनांक 3 मार्च 2017 को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे को अधिसूचित किया था। ढांचे को प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता के अनुसार और वर्ष 2020 और 2022 में जारी संशोधनों के माध्यम से हितधारकों के समक्ष होने वाली चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया था।

3. हितधारकों नामतः, प्रसारकों, एमएसओ, डीटीएच ऑपरेटरों और एलसीओ ने समय-समय पर प्राधिकरण के विचारार्थ अन्य मुद्दे उठाए|

4. ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए, प्राधिकरण ने दिनांक 8 अगस्त 2023 को "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा" पर परामर्श पत्र जारी किया जिसमें हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गईं।

5. उक्त परामर्श पत्र में विभिन्न हितधारकों से कई मुद्दों पर टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए थे, जिनमें नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ), टीवी चैनलों के वितरकों (वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों-डीपीओ) द्वारा बुके के एमआरपी तय करने के लिए ए-ला-कार्टे चैनलों के एमआरपी के योग पर छूट की सीमा, क्षमता गणना के लिए एसडी चैनलों के संदर्भ में एचडी चैनल की समतुल्यता, डीपीओ द्वारा गठित सभी पैक्स में अनिवार्य एफटीए समाचार चैनल, डीडी फ्री डिश के साथ समान अवसर, रेफेरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर में संशोधन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में चैनलों की सूची, एमएसओ और

एलसीओ के बीच राजस्व साझाकरण, कैरिज शुल्क, मौजूदा इंटरकनेक्शन करार की समाप्ति के बाद चैनलों को हटाना, बिलिंग चक्र से संबंधित मुद्दे, प्लेटफॉर्म सेवा चैनलों का विनियम, निर्धारित शुल्क की समीक्षा, उपभोक्ता कॉर्नर, डीपीओ द्वारा वेबसाइटों की स्थापना, अभ्यास मैनुअल आदि शामिल हैं।

6. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों और खुला मंच चर्चा के दौरान हुई चर्चा का विश्लेषण किया और कई प्रसारकों, डीपीओ (एमएसओ/डीटीएच/एचआईटीएस/आईपीटीवी) और एलसीओ की उपस्थिति के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा के स्तर को नोट किया। तदनुसार, सेवा प्रदाताओं को गतिशील बाजार स्थितियों को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए लचीलापन प्रदान करने की आवश्यकता है,साथ ही इसमें उपभोक्ताओं और छोटे खिलाड़ियों के हितों की रक्षा पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता के माध्यम से की जानी चाहिए।

7. उपर्युक्त विचारों के आधार पर, भादूविप्रा ने टैरिफ ऑर्डर 2017, अंतर्संयोजन विनियम, 2017 और क्यूओएस विनियम, 2017 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। इन संशोधनों का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित है:

क. विनियामक अनिवार्यताओं और अनुपालन आवश्यकताओं को कम करके प्रसारण क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाना।

ख. पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता के माध्यम से उपभोक्ताओं और छोटे प्लेयर्स के हितों की रक्षा करते हुए सेवा प्रदाताओं को बाजार संचालित दृष्टिकोण अपनाने के लिए लचीलापन प्रदान करना।

ग. विनियामक प्रावधानों को सरल बनाकर व्यापार करने में सुविधा प्रदान करना।

8. इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

क. टैरिफ आदेश

i. नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) पर 200 चैनलों के लिए 130 रुपये और 200 से अधिक चैनलों पर 160 रुपये की सीमा को हटा दिया गया है और इसे बाजार संचालित और न्यायसंगत बनाने के लिए सहिष्णुता (फॉरबियरेंस) के तहत रखा गया है। सेवा प्रदाता अब चैनलों की संख्या, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न ग्राहक वर्गों या इनके किसी भी संयोजन के आधार पर अलग-अलग एनसीएफ चार्ज कर सकते हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे सभी शुल्कों को सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए और भादूविप्रा को रिपोर्ट करने के अलावा उपभोक्ताओं को सूचित किया जाना चाहिए।

ii. डीपीओ को अब अपने बुके बनाते समय 45% तक की छूट देने की अनुमति दी गई है, ताकि बुके बनाने में उन्हें लचीलापन मिल सके और उपभोक्ताओं को आकर्षक डील्स की पेशकश की जा सके। पहले यह छूट केवल 15% तक की ही दी जाती थी।

iii. सार्वजनिक सेवा प्रसारक के डीटीएच प्लेटफॉर्म पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के उपलब्ध पे चैनल को प्रसारक द्वारा सभी एड्रेसेबल वितरण प्लेटफॉर्म के लिए फ्री-टू-एयर घोषित करना होगा, ताकि सभी को समान अवसर मिल सके।

iv. डीपीओ को अपने प्लेटफॉर्म सेवाओं के टैरिफ की घोषणा करने का आदेश दिया गया है।

ख. अंतर्संयोजन विनियम

i. एचडी टेलीविजन सेटों के प्रसार और उच्च परिभाषा सामग्री के प्रसारण को प्रोत्साहित करने के लिए, कैरिज शुल्क के उद्देश्य से एचडी और एसडी चैनलों के बीच अंतर को हटा दिया गया है।

ii. कैरिज शुल्क व्यवस्था को सरल बनाया गया है और कैरिज शुल्क के लिए केवल एक ही सीमा निर्धारित करके प्रौद्योगिकी तटस्थ बनाया गया है, जिससे डीपीओ को उचित समझे जाने पर कम कैरिज शुल्क लेने का विकल्प प्रदान किया गया है।

iii. उपर्युक्त उपायों से न केवल उपभोक्ताओं के लिए सेवा प्रदाताओं के प्रस्ताव को सरल बनाने की उम्मीद है, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले चैनलों की उपलब्धता को भी बढ़ावा मिलेगा।

ग. गुणवत्ता सेवा (क्यूओएस) विनियम

i. स्थापना और सक्रियण, विजिटिंग, स्थानांतरण और अस्थायी निलंबन जैसी सेवाओं के लिए शुल्क जो पहले विनियम के तहत निर्धारित किए गए थे, फॉर्बेरन्स के तहत रखे गए हैं। उपभोक्ताओं को स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए डीपीओ को अपनी सेवाओं के शुल्क प्रकाशित करने होंगे।

ii. छोटे डीपीओ के लिए कुछ विनियामक अनुपालन में छूट है।

iii. उपभोक्ताओं को अधिक स्पष्टता के लिए सभी प्रीपेड सब्सक्रिप्शन की डुरैशन/अवधि/वैधता केवल दिनों की संख्या में निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

iv. डीपीओ इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में चैनलों के लिए एमआरपी के साथ वितरक खुदरा मूल्य (डीआरपी) प्रदर्शित कर सकते हैं।

v. डीपीओ ईपीजी में 'प्लेटफॉर्म सेवाओं' की शैली के तहत प्लेटफॉर्म सेवा चैनलों को वर्गीकृत करेंगे।

vi. डीपीओ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्लेटफॉर्म सेवा के खिलाफ ईपीजी में प्लेटफॉर्म सेवा चैनल के संबंधित एमआरपी प्रदर्शित करेंगे।

vii. डीपीओ किसी भी प्लेटफॉर्म सेवा के सक्रियण/निष्क्रियण का विकल्प प्रदान करेंगे।

घ. सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ आदेश के प्रावधानों और अंतर्संयोजन विनियमन और क्यूओएस विनियमन के कुछ अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के लिए वित्तीय निरुत्साहन पेश किया गया है।

ङ. सेवा प्रदाताओं को टैरिफ और अन्य शुल्कों से संबंधित सभी जानकारी, जिन्हें अब रोक दिया गया है, अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित करना होगा। इसके अलावा, उन्हें सब्सक्राइब किए जा रहे प्लान से संबंधित टैरिफ और अन्य शुल्कों के बारे में सब्सक्राइबर्स को बताना होगा।

9. इसके अलावा, प्राधिकरण ने परामर्श प्रक्रिया में शामिल कुछ मुद्दों पर एमआईबी को अनुशंसाए भी जारी कीं। इन मुद्दों में 'इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड में चैनलों की सूचीबद्ध करने' और 'डीडी फ्री डिश' को एड्रेसेबल प्रणाली में बदलना शामिल है। इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क. ईपीजी में चैनलों की सूची बनाना: प्रत्येक चैनल को अनुमति देते समय, एमआईबी अंतर्संयोजन विनियम 2017 के अनुसार प्रत्येक चैनल की प्राथमिक भाषा और प्रत्येक गैर-समाचार चैनल की उप-शैली के बारे में प्रसारकों से जानकारी मांगेगा और एमआईबी के प्रसारण सेवा पोर्टल पर इसे प्रदर्शित करेगा, ताकि डीपीओ वर्तमान विनियमन के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा आसान नेविगेशन के लिए चैनल को ईपीजी में उचित स्थान पर रख सकें।

ख. डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को एड्रेसेबल प्रणाली में अपग्रेड करना:

i. देखने के अनुभव की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, पायरेसी से निपटने के लिए टेलीविजन चैनलों के अनधिकृत पुनः प्रसारण को रोकने और ग्राहकों का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए, प्रसार भारती डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म को गैर-एड्रेसेबल प्रणाली से एड्रेसेबल प्रणाली में बदलने के लिए कदम उठाएगा और अपलिंकिंग से पहले डीडी फ्री डिश हेडएंड पर निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के सिग्नल को एन्क्रिप्ट करके शुरुआत करेगा। इसके बाद, डीडी फ्री डिश के अन्य सभी चैनल भी एन्क्रिप्टेड फॉर्म में प्रसारित किए जा सकते हैं।

ii. सार्वजनिक सेवा प्रसारक को भादूविप्रा विनियमों की अपेक्षित छूट प्रदान की जाएगी, जब तक ऐसी अधिसूचना एमआईबी द्वारा जारी कर दी जाती है ।

iii. प्रसार भारती कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस), सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) और इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) के लिए स्वदेशी तकनीकों का उपयोग कर सकता है।

iv. प्रसार भारती को डीडी फ्री डिश के लिए इंटरऑपरेबल एसटीबी को अपनाना चाहिए, ताकि पूरे इकोसिस्टम को ऑपरेटर-आधारित एसटीबी से इंटरऑपरेबल एसटीबी में बदलने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जा सके, ताकि उपभोक्ताओं की पसंद को और सशक्त बनाया

जा सके। इससे हर बार सेवा प्रदाता बदलने पर एसटीबी बदलने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

v. डीडी फ्री डिश को गैर-एड्रेसेबल से एड्रेसेबल प्लेटफॉर्म में बदलने के साथ-साथ एसटीबी की बिक्री और बिक्री उपरांत सेवा के लिए प्रसार भारती द्वारा निर्माताओं और वितरकों को अधिकृत करने के लिए एक रोडमैप का सुझाव एमआईबी को दिया गया है।

vi. एमआईबी निजी डीपीओ को इंटरऑपरेबल एसटीबी अपनाने और लागू करने का निर्देश दे सकता है।

10. भादूविप्रा ने वर्तमान संशोधनों में उन मुद्दों को संबोधित किया है जिन्हें दिनांक 8 अगस्त 2023 के परामर्श पत्र में शामिल किया गया था। तथापि, इन संशोधनों के लिए परामर्श प्रक्रिया के दौरान, विभिन्न हितधारकों द्वारा कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए गए थे, जिन पर भादूविप्रा के विचार के लिए विस्तृत परामर्श प्रक्रिया से गुजरना होगा। इन मुद्दों और सुझावों पर ध्यान दिया गया है और भादूविप्रा जल्द ही प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक परामर्श पत्र जारी करेगा।

11. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस), भादूविप्रा से ईमेल आईडी: advbcs-2@trai.gov.in या टेलीफोन +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा

****